नई दिल्ली, रविवार
15 सितंबर 2019
नोएडा
मूल्य ₹ 5.00
पृष्ठ 18+8+6=32

दैनिक जागरण

www.jagran.com

दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और प. बंगाल से प्रकाशित

एनपीए अकाउंट, एनसीएलटी खरीदारों के लिए है रोड़ा

नोएडा में आम्रपाली, जेपी, थ्री सी समेत आठ बिल्डरों का एनसीएलटी में है केस

कुंदन तिवारी ● नोएडा

बिल्डर वित्तमंत्री के एलान से खुश, सभी बिल्डर का बैंक अकाउंट एनपीए है, बिल्डरों ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया

60 फीसद तक पूरी हो चुकी बिल्डर परियोजनाओं या उसके बाद जो लटक गई हैं उनको केंद्र सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये का फंड देने की घोषणा की। इससे आवास क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।

वित्तमंत्री की ओर से लिया गया यह निर्णय स्वागत योग्य है। कई मध्य आय और किफायती आवास परियोजनाएं, जो धन की कमी के कारण धीमी प्रगति में देख जा रही थीं। उन्हें 10,000 करोड़ रुपये की विशेष विंडो स्थापित करने के परिणाम स्वरूप तेज किया जा सकेगा। करीब 3 से 3.5 लाख आवास यूनिट के तेजी से खरीदारों को वितरण में मदद करेगा। हालांकि इसमें एक शर्त यह है कि परियोजना नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी)में न हो, बिल्डर का अकाउंट एनपीए (नॉन परफार्मिंग एसेट) न हुआ हो। सरकार के इस एलान से दिल्ली-एनसीआर में अपने घर का इंतजार कर रहे हजारों खरीदारों को लाभ मिल सकता है, लेकिन इनसे अधिक खरीदारों को अभी भी आशियाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि नोएडा में आम्रपाली, जेपी, थ्री सी समेत आठ बिल्डरों की परियोजनाएं एनसीएलटी में विचाराधीन हैं, इसलिए सरकार की राहत का लाभ इन परियोजनाओं के खरीदारों को नहीं मिल सकता है। खरीदारों का कहना है कि नोएडा में 10 वर्ष से दो लाख खरीदार आशियाने का इंतजार कर रहे हैं। सड़क से संसद और सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष कर रहे हैं। सरकार से लगातार स्ट्रेस फंड की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक हमारी परेशानियों को सरकार समझ ही नहीं सकी है। रियल एस्टेट सेक्टर को गति देने के लिए केंद्र सरकार का फैसला कई ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं के लिए संजीवनी साबित हो सकता है।

आवास क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वित्तमंत्री की ओर से यह निर्णय वास्तव में स्वागत योग्य है। कई मध्य-आय और किफायती आवास परियोजनाएं जो धन की कमी के कारण धीमी प्रगति देख रही हैं, उन्हें 10,000 करोड़ रुपये की विशेष विंडो स्थापित करने के परिणाम स्वरूप तेज किया जाएगा। **-मनोज गौड़, एमडी,** गौर्स ग्रुप व चेयरमैन अफोर्डेबल हाउसिंग कमेटी क्रेडाई

10 साल के टी-बिल पर प्रचलित उपज 6.6 से 6.7 फीसद के आसपास मंडरा रही है। हाउस बिल्डिंग एडवांस को इससे जोड़ने का सरकार का फैसला प्रभावी रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए ब्याज दर में कमी की संभावना है, जो घर खरीदारों का सबसे बड़ा हिस्सा रहेगा।

-दीपक कपूर, निदेशक, गुलशन होम्स

वित्त मंत्री ने अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ईसीबी दिशा-निर्देशों में छूट की घोषणा की। घर खरीदारों के लिए वित्तपोषण को कम करके, सरकार ने तेजी से बिक्री और प्रोजेक्ट के पजेशन का मार्ग आसान किया है।

-अशोक गुप्ता, सीएमडी, अजनारा इंडिया लिमिटेड

60 प्रतिशत पूरी होने वाली परियोजनाओं को विशेष विंडो के माध्यम से फंडिंग मिलेगी। इस फैसले से लगभग 3.5 लाख अटकी यूनिट लाभांवित होंगी। कई खरीदारों को जल्द ही अपने घरों का कब्जा मिल जाएगा।

-सागर सक्सेना, प्रोजेक्ट हेड, स्पेक्ट्रम मेट्रो